● वर्ष : 05 ● अंक : 25

● गाजियाबाद, मंगलवार 19 मई 2026

● पृष्ठ-6 ● मूल्य : दो रूपये

● RNI No. - UPHIN/2022/84480

E-mail: swastiksaharanews@gmail.com

www.swastiksahara.com

नई दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित   हिन्दी दैनिक

चींटी से अच्छा उपदेशक कोई और नहीं है। वह काम करते हुए खामोश रहती है।

'प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे...'

सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी का 'शिफ्ट सिस्टम' प्लान

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमाज नियमित रूप से अदा की जानी चाहिए और जनता की असुविधा से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर इसे बारी-बारी से भी अदा किया जा सकता है। लखनऊ में एक जनसभा में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन पहले समझाने-बुझाने के जरिए ही लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आपको नमाज अदा करनी ही होगी, आप अपनी बारी में पढ़ सकते हैं.. हम आपको प्यार से मना लेंगे, अगर आप नहीं मानते हैं, तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कें आवागमन के लिए हैं और सड़कों पर नमाज पढ़कर यातायात अवरुद्ध करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में लोग सचमुच सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता - जाकर खुद देख लीजिए। सड़कें आवागमन के लिए हैं। क्या कोई भी चौराहे पर आकर तमाशा खड़ा कर यातायात अवरुद्ध कर सकता है? सार्वजनिक आवागमन में बाधा डालने का किसी को क्या अधिकार है? मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि यदि आवश्यक हो तो बारी-बारी से नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा, 'यह कैसे संभव होगा, हमारी संख्या बहुत अधिक है?' हमने जवाब दिया कि बारी-बारी से नमाज पढ़ी जा सकती है। यदि घर में जगह नहीं है, तो उसी के अनुसार संख्या का प्रबंधन करें। अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार का शासन ही कानून का शासन है। यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। नमाज पढ़ना अनिवार्य है - आप अपनी ड्यूटी के दौरान पढ़ सकते हैं। हम इसे रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।

मुख्यमंत्री योगी ने पहले भी इसी तरह के बयान दिए हैं, खासकर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि हिंदू त्योहारों से पहले कर्फ्यू लगाया जाता है। उन्होंने लगातार यह बात दोहराई है कि सार्वजनिक सड़कों और बुनियादी ढांचे का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे यातायात या दैनिक आवागमन बाधित हो।

मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों पर पथराव, खिड़कियों के शीशे टूटे

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए, जिससे कई डिब्बों के शीशे टूट गए और यात्रियों में दहशत फैल गई। पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26501) को मझौलिया और खबरा इलाकों के पास निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन के तीन डिब्बों के शीशे इस घटना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद यात्रियों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सूचना दी।

बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेल खंड पर एक यात्री ट्रेन में आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। खबरों के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 6 बजे हुई जब आरा होते हुए सासाराम से पटना जा रही एक यात्री ट्रेन में अचानक आग लग गई। एक डिब्बे में आग लगने से ट्रेन में सवार यात्री और प्लेटफार्म पर मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। सौभाग्य से, आग पर काबू पा लिया गया है।

दो अन्य ट्रेनों को निशाना बनाया गया

वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना के कुछ ही समय बाद, उसी रेल मार्ग पर चलने वाली दो और ट्रेनों पर हमला हुआ। पटना–जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस (15550) और लिच्छवी एक्सप्रेस (14006) को भी निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमलों में दोनों ट्रेनों के कई डिब्बों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए।

मोदी की अपील का दिख रहा असर, दिल्ली में कलेक्टर ने सरकारी गाड़ी छोड़ अपनाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई मितव्ययता, ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली में इसका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब दिल्ली वेस्ट के जिलाधिकारी आईएएस हरी कल्लिकट ने सरकारी गाड़ियों के बजाय मेट्रो से सफर कर कार्यालय पहुंचने का निर्णय लिया।

जानकारी के अनुसार, 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हरी कल्लिकट अपने जीके-1 स्थित आवास से राजौरी गार्डन स्थित डीएम कार्यालय तक दिल्ली मेट्रो और ई-रिक्शा से यात्रा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों के बीच सफर कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और ईंधन बचत का संदेश दिया।

मीडिया से बातचीत में कलेक्टर हरी कल्लिकट ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए ईंधन बचत समय की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की।

यात्रियों और स्थानीय लोगों ने उनके इस कदम की सराहना करते हुए इसे सादगी, जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल बताया। लोगों का कहना है कि यदि वरिष्ठ अधिकारी भी सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, तो इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा और ईंधन बचत के साथ ट्रैफिक कम करने में भी मदद मिलेगी।

मूलतः केरल राज्य से आने वाले हरी कल्लिकट की यह पहल प्रशासनिक सादगी, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार का संदेश देने वाली मानी जा रही है।

सोशल मीडिया पर भी लोग उनके इस कदम की प्रशंसा करते हुए इसे जनभागीदारी और जिम्मेदार प्रशासन का उदाहरण बता रहे हैं। इससे पूर्व चंडीगढ़ में अपनी तैनाती के दौरान अलग अलग पदों पर रहते हुए इन्होंने अपनी सादगी और सख़्त छवि से एक मजबूत छाप छोड़ी।

नीट-यूजी विवाद के बीच नया तूफान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जयराम रमेश का विशेषाधिकार नोटिस

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल किया है, जिसमें उन पर संसद और उसकी समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों का आरोप लगाया गया है। यह नोटिस राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 187 के तहत दाखिल किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रमेश ने लिखा कि मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ संसद और संसदीय समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में राज्य परिषद की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 187 के तहत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। रमेश ने आगे आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां तब की गईं जब मंत्री शिक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की अध्यक्षता कर रहे थे, जो देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। विशेषाधिकार नोटिस प्रधान द्वारा नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान की गई टिप्पणियों से संबंधित है। उनसे शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था। नोटिस के अनुसार, प्रधान ने कहा कि मैं संसदीय स्थायी समिति की चेतावनियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति/राधाकृष्णन समिति के बारे में बात करूंगा। संसदीय स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्य हैं। वे चीजों को एक विशेष तरीके से लिखते हैं, यह आप भी जानते हैं। इसलिए, मैं स्थायी समिति पर कुछ नहीं बोलूंगा। रमेश ने इन टिप्पणियों को अत्यंत निंदनीय और बेहद अपमानजनक बताते हुए कहा कि इनसे संसदीय संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है।

बंगाल में महिलाओं को डबल तोहफा, अन्नपूर्णा योजना से मिलेंगे रु 3000, सरकारी बसों में यात्रा फ्री

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने महिलाओं को एक जून से 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा योजना को सोमवार को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी अनुमति दे दी। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।

मंत्री पॉल ने कहा, ''मंत्रिमंडल ने एक जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने एक जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।''

प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, अनिश्चितकाल के लिए रुकी पदयात्रा

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

वृंदावन। वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य एक बार फिर से बिगड़ गया है। इसकी वजह से उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं उनके दर्शन भी रोक दिए गए हैं। इसके बाद हजारों श्रद्धालु निराश हैं। रविवार की देर रात बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज हमेशा की तरह सुबह 3 बजे पदयात्रा के लिए रवाना नहीं हुए। आश्रम से उनके शिष्य उनकी जगह आए और लाउडस्पीकर के जरिये भक्तों को इसकी जानकारी दी।

शिष्यों ने बताया कि महाराज जी की अस्वस्थता के कारण आज से होने वाली पदयात्रा स्थगित की जा रही है। श्रद्धालुओं से सड़क किनारे भीड़ न लगाने और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस घोषणा के बाद भक्तों को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। आश्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि महाराज जी पिछले करीब 21 सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।

हरिद्वार में मचा हड़कंप! 'हर की पौड़ी' को बम से उड़ाने की धमकी, साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार में सोमवार को उस समय भारी सनसनी और दहशत फैल गई, जब एक अज्ञात कॉलर ने प्रसिद्ध 'हर की पौड़ी' घाट को बम से उड़ाने की खौफनाक धमकी दी। पुलिस के आपातकालीन नंबर पर सीधे आए इस कॉल के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस धार्मिक स्थल की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया। अधिकारियों के अनुसार, नशे में धुत एक व्यक्ति ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल किया और दावा किया कि चार दिनों के भीतर हर की पौड़ी और कई अन्य जगहों पर बम धमाके किए जाएँगे। इस कॉल के बाद पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया और तत्काल कई टीमों को सक्रिय कर दिया गया। कॉलर का फोन नंबर और लोकेशन तुरंत ट्रेस कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया; उसकी पहचान पौड़ी जिले के यमकेश्वर निवासी 30 वर्षीय सोहन सिंह रावत के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने नशे की हालत में यह धमकी दी थी।

हर की पौड़ी का इतना अधिक महत्व क्यों है?

हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पूजनीय घाट है और यह पूरे भारत तथा विदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माना जाता है कि इस घाट का संबंध भगवान विष्णु से है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र डुबकी लगाने को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाला मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर शाम के समय होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।

केरलम में मुख्यमंत्री सतीशान का आते ही एक्शन शुरू: महिलाओं को फ्री बस, आशा वर्कर्स को 3000 की सौगात

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। नव नियुक्त केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशान की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में, यूडीएफ सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त केएसआरटीसी बस यात्रा, बुजुर्ग कल्याण के लिए एक समर्पित विभाग और आशा कार्यकताओं के मानदेय में 3,000 की वृद्धि की घोषणा की।

मंत्रिमंडल ने 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं पर हुए कथित हमले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकताओं के मानदेय में 3,000 की मासिक वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो सचिवालय के बाहर उनके लंबे विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए वादे को पूरा करती है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं, स्कूल के रसोइया कर्मचारियों, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आयाओं के मानदेय में भी 1,000 की मासिक वृद्धि की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

केरल को वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करके एक आदर्श सभ्य समाज बनना चाहिए। कैबिनेट ने वरिष्ठ विधायक जी सुधाकरन को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया और राज्यपाल से विधायकों के शपथ ग्रहण और अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, विधायक 21 मई को शपथ लेंगे, जबकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 22 मई को होंगे। इससे पहले दिन में, सतीशान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो 2026 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद एक दशक बाद केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी का प्रतीक है।

राहुल गांधी ने सतीशान को बधाई दी

तिरुवनंतपुरम में शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी ने सतीशान और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देते हुए कहा कि नई सरकार जनता की आवाज का अनुसरण करेगी। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की जीत जनता के जनादेश को दर्शाती है और उन्होंने नए प्रशासन पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि केरल की जनता ने इस सरकार के लिए संघर्ष किया है। उनकी आवाज ही इसका मार्गदर्शन करेगी। वीडी सतीशान जी और पूरे मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई, जो अब हर केरलवासी की आवाज का प्रतिनिधित्व करेंगे।

छत्तीसगढ़ पुलिस अब होगी हाईटेक, अमित शाह ने दी 400 डायल-112 वाहनों की सौगात

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई, 2026 को रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस की उन्नत सीजी डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा और मोबाइल फोरेंसिक वैन के बेड़े का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की उपस्थिति में, श्री शाह ने राज्य भर में आपातकालीन सेवाओं और फोरेंसिक जांच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 400 उन्नत डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों और 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन का उद्घाटन किया।

'एकके नंबर, सब्बो बार' थीम के तहत शुरू की गई यह नई आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, संकट के समय त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा आपात स्थितियों को एक ही मंच पर एकीकृत करती है। नए तैनात किए गए 400 वाहन स्मार्टफोन, जीपीएस सिस्टम, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरे, डैश कैमरे, मोबाइल एनवीआर सिस्टम और सौर बैकअप सुविधाओं से लैस हैं, जो आपातकालीन अभियानों के दौरान लाइव निगरानी, वास्तविक समय ट्रैकिंग और त्वरित संचार को सक्षम बनाते हैं।

यह सेवा जीआईएस आधारित निगरानी, उन्नत वाहन ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक तकनीक और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान का उपयोग करके निरंतर संचालित होगी। सभी 33 जिला समन्वय केंद्र नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नागरिक वॉइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट सेवाओं और एसओएस-112 इंडिया मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जनता दर्शन में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने सुनीं जनसमस्याएं

बाइक शेयरिंग के माध्यम से ईंधन संरक्षण का दे रहे संदेश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ह्लजनता दर्शनह्व कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा किया जाए।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार ह्लजनता दर्शनह्व और जनसुनवाई कार्यक्रम की सीधी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से की जा रही है। इसी के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आमजन की शिकायतें सुनने और जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। साथ ही जूम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर उन्हें शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ईंधन संरक्षण के संदेश को अपनाते हुए स्वयं भी बाइक शेयरिंग के माध्यम से कार्यालय आना-जाना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है।

‘बच्चों की जिज्ञासा पर खुश हुए डीएम, बोलेः तुम भी बन सकते हो बड़े अधिकारी’

डीएम रविन्द्र मांदड़ ने बच्चों संग बिताए यादगार पलः दिया सफलता का मंत्र

मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जहां आज की युवा पीढ़ी और बच्चे आभासी दुनिया में उलझते जा रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे आज भी ज्ञान, समझ और प्रशासनिक व्यवस्था को जानने की उत्सुकता रखते हैं। ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य उस समय देखने को मिला जब विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान के नातिन नव्या, मिस्टी और पोतो वियान शर्मा, अयान शर्मा ने उनसे सवाल किया ‘डीएम क्या होता है?’ जैसा सवाल पूछ लिया। बच्चों की मासूम जिज्ञासा को गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान ने उन्हें बेहद सरल भाषा में समझाया कि डीएम यानी जिलाधिकारी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो पूरे जिले की व्यवस्था संभालता है। लेकिन बच्चों की उत्सुकता यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी से मिलने की इच्छा जता दी। बच्चों की इस मासूम जिद को पूरा करने के लिए ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान उन्हें सीधे जिलाधिकारी कार्यालय लेकर पहुंचे। जैसे ही जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ को पता चला कि कुछ छोटे बच्चे उनसे मिलने आए हैं, उन्होंने तुरंत अपने कार्यालय में बुलाया और बड़े स्नेह के साथ उनका स्वागत किया। बच्चों ने जिलाधिकारी को गुलाब का फूल भेंट कर उनसे कई रोचक सवाल पूछे। जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने भी बच्चों के हर सवाल का बेहद सहज और आत्मीयता से जवाब दिया। बातचीत के दौरान जब जिलाधिकारी ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चों ने उत्साह से कहा कि हम भी आपकी तरह बड़े अधिकारी बनेंगे। मासूम बच्चों के सपनों और उत्साह को देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे। इस अवसर पर ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के मन में अच्छे संस्कार और बड़े सपने जगाना ही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह मुलाकात न सिर्फ बच्चों के लिए यादगार बनी, बल्कि यह संदेश भी दे गई कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलने पर आज की पीढ़ी देश का भविष्य बदल सकती है।

नगर निगम अपने संसाधनों का उपयोग कर नालों की करा रहा है सफाई

नालों से निकली सिल्ट को उठाने में ना हो देरीः नगर आयुक्त

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा पांचों जोन अंतर्गत अभियान के रूप में नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है जिसके क्रम में बड़े एवं छोटे नालों को साफ कराया जा रहा है जिसकी मॉनिटरिंग भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार नालों की सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है गाजियाबाद नगर निगम के संसाधनों का उपयोग करते हुए नालों की सफाई कराई जा रही है बड़ी पोर्कलेन, बड़ी जेसीबी का उपयोग करते हुए बड़े नालों की सफाई का कार्य चल रहा है इसी प्रकार छोटे नालों की सफाई के लिए छोटी पोर्कलेन मशीन लगाई गई है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा बताया गया मोहन नगर जोन अंतर्गत शालीमार गार्डन गणेशपुरी, कुटी रोड,जवाहर पार्क अर्थला, पसौंडा क्षेत्र में नाला सफाई का कार्य चल रहा है, सिटी जोन अंतर्गत केला भट्टा नंदग्राम मैंन रोड, पंचवटी, राकेश मार्ग के नालों की सफाई का कार्य चल रहा है, कवि नगर क्षेत्र में रईसपुर, राज नगर, रजापुर, संजयनगर में नाला सफाई का कार्य किया जा रहा है, विजयनगर जोन में क्रॉसिंग रिपब्लिक डूंडाहेड़ा गौशाला फाटक, सर्वोदय नगर, प्रताप विहार सम्राट चौक में पुलियाओं की सफाई और नाला सफाई का कार्य चल रहा है, इंदिरापुरम सहित वसुंधरा जोन में भी नाला सफाई का कार्य अभियान के रूप में चल रहा है जिसमें सेक्टर एक कनवानी पुलिया सेक्टर 2 वसुंधरा में नाला सफाई का कार्य चल रहा है वैशाली सेक्टर 4 और कौशांबी क्षेत्र में भी नाला सफाई का कार्य चल रहा है इंदिरापुरम क्षेत्र में अभय खंड अहिंसा खंड में नाला सफाई का कार्य चल रहा है।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया अपने निगम के संसाधनों का उपयोग करते हुए नाला सफाई का कार्य कराया जा रहा है आवश्यकता को देखते हुए निविदा प्रक्रिया पर जाया जाएगा, बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग करते हुए नाला सफाई का कार्य किया जा रहा है संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं ट्रैफिक या अन्य को असुविधा न हो ध्यान रखा जा रहा है नाला सफाई के साथ-साथ पुलियाओं की भी सफाई की जा रही है जल प्रवाहित रहे विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसके अलावा नालों से निकलने वाली सिल्ट को भी तद दिवस में ही उठाया जाए निर्देश दिए गए हैं नालों की सिल्ट उठने में किसी प्रकार की लापरवाही और देरी न हो विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है।

लोनी में 4.65 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने सोमवार को नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में करीब 4 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वार्ड संख्या 52, 51, 53, 39 और 32 के रूप नगर, प्रेम नगर ए-ब्लॉक, जमालपुरा, राशिद अली गेट, जैन कॉलोनी और गढ़ी जस्सी सहित कई स्थानों पर नारियल फोड़कर व रिबन काटकर कार्यों की शुरूआत की गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर नगर पालिका अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया।

रंजीता धामा ने कहा कि इन विकास कार्यों में प्रेम नगर में पाइपलाइन बिछाने, श्मशान घाट के रखरखाव, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने और आरसीसी नालियों के निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोनी नगर पालिका क्षेत्र तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है और विभिन्न गलियों व मुख्य मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की सूरत लगातार बदल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोनी नगर पालिका क्षेत्र और अधिक सुंदर व व्यवस्थित बनेगा, जिसमें क्षेत्र की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

इस मौके पर सभासद नगमा वारसी, एडवोकेट शांतनु, राहुल अली, पूर्व सभासद योगेश, राशिद वारसी, इसरार बेग, कम्मन चौधरी, मोहम्मद अली, शकील धामा, मोहसिन मलिक, सिराज मलिक, अजहर मलिक, इंतजार, शराफत, हाजी इलियास, अबदुल्ला, इमसाद सलमानी, तपसीर मलिक, सलमान, जावेद, मुमताज, दिलशाद मलिक, अल्लाबंदी, सीमा, संजुम, फरीदा, रूखसाना, प्रवीन, अफसाना सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

आरकेजी ग्लोबल स्कूल में समर कैंप 2026 का भव्य उद्घाटन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। आर.के.जी. ग्लोबल स्कूल में समर कैंप 2026 का शुभारंभ बड़े उत्साह, उमंग एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की वाइस चेयरवुमन श्रीमती आँचल गोयल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर प्रिंसिपल कैप्टन डॉ. दिनिशा भारद्वाज सिंह भी उपस्थित रहीं। उद्घाटन समारोह में विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं अभिभावकों की विशेष उपस्थिति देखने को मिली। सभी ने समर कैंप के शुभारंभ का गर्मजोशी से स्वागत किया।

विद्यालय परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना रहा। समर कैंप के प्रथम दिवस पर विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ नृत्य, कला एवं शिल्प, खेल-कूद, योग, संगीत तथा रचनात्मक शिक्षण गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के साथ-साथ मनोरंजन एवं अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कैंप का वातावरण उत्साह, खुशी एवं रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर दिखाई दिया।

समर कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण सत्र रहा, जो बच्चों एवं अभिभावकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कोच नीरज गहलोत द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को आत्मरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण गुर सिखाए गए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने दैनिक जीवन में सुरक्षा के उपाय, कठिन परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने की तकनीकें तथा आत्मविश्वास बनाए रखने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस प्रशिक्षण सत्र में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और आत्मरक्षा तकनीकों को सीखने में विशेष रुचि दिखाई। सभी प्रतिभागियों ने इस सत्र को अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर प्रिंसिपल कैप्टन डॉ. दिनिशा भारद्वाज सिंह ने विद्यार्थियों को समर कैंप की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि तथा नई क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यार्थियों ने भी पूरे जोश, अनुशासन एवं आनंद के साथ सभी गतिविधियों में सहभागिता कर समर कैंप के पहले दिन को यादगार बना दिया।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि समर कैंप के समापन अवसर पर एक भव्य ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की विभिन्न प्रस्तुतियाँ एवं विशेष कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। यह समापन समारोह 23 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। विद्यालय परिवार ने आशा व्यक्त की कि समर कैंप 2026 विद्यार्थियों के लिए सीखने, मनोरंजन, रचनात्मकता एवं आत्मविकास का एक उत्कृष्ट मंच सिद्ध होगा तथा आने वाले दिनों में भी विद्यार्थी इसी उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते रहेंगे।

पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा में सीडीओ ने जताई नाराजगी

लक्ष्य के मुकाबले धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगाई फटकार, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ की अध्यक्षता में सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार प्रगति, बैंकिंग ऋण वितरण, प्रचार-प्रसार और फील्ड स्तर की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान योजना की धीमी प्रगति और लंबित प्रकरणों पर सीडीओ ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग लक्ष्य पूर्ति के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में डिस्कॉम अधिकारियों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि फील्ड स्टाफ, लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से गांव-गांव तथा वार्ड स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना से जुड़ सकें।

बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि कई मामलों में ऋण स्वीकृत होने के बावजूद बैंकों द्वारा समय से धनराशि का वितरण नहीं किया गया है। इस पर सीडीओ ने एलडीएम को निर्देश दिए कि दो दिन के भीतर लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही परियोजना अधिकारी जावेद खान को निर्देशित किया गया कि डिस्कॉम, बैंक और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा करें और योजना की प्रगति में तेजी लाएं।

सीडीओ ने शिक्षा विभाग को विद्यालयों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी ग्राम प्रधानों को योजना के प्रति जागरूक करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने को कहा। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाए और शासन के निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शहर में जगह- जगह लगे अवैध पोस्टर हटाएं जाएंः नीरज गोयल

गाजियाबाद (स्वास्तिक सहारा)। पार्षद नीरज गोयल ने सरकारी एवं निजी भवनों की दीवारों, डिवाइडरों तथा बिजली के पोलों पर लगाए जा रहे अवैध पोस्टरों की रोकथाम को लेकर नगरायुक्त के नाम पत्र लिखकर अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद नगर में समय-समय पर मनोरंजन हेतु मेले, सर्कस एवं जादूगरों के शो आयोजित होते रहते हैं, जिनका शहर की जनता एवं बच्चे उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं तथा उनका आनंद भी लेते हैं। किन्तु देखने में आता है कि मेला आयोजक, सर्कस संचालक एवं जादूगर अपने प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी एवं निजी भवनों की दीवारों, डिवाइडरों तथा

बिजली के पोलों पर बड़ी संख्या में पोस्टर एवं विज्ञापन चस्पा कर देते हैं। एक ही दीवार पर अनगिनत संख्या में पोस्टर चिपका देते हैं। ये आयोजन भले ही सीमित समय के लिए होते हों, लेकिन इनके समाप्त होने के बाद भी पोस्टर लंबे समय तक लगे रहते हैं, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है तथा गंदगी फैलती है। नीरज गोयल ने कहा कि निगम एक्ट के अनुसार किसी भी प्रकार का विज्ञापन नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के अवैध पोस्टर ह्लस्वच्छ एवं सुंदर गाजियाबादह्व अभियान की भावना के विपरीत हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध पोस्टर एवं विज्ञापनों को तत्काल हटाया जाए, जिससे गाजियाबाद नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाया जा सके।

एसडीएम ने लोनी में सीवर लाइन और सड़क निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। तहसील लोनी क्षेत्र में जल निगम द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे दिल्लीझ्रसहारनपुर मार्ग के निर्माण तथा लोनी तिराहे के आसपास फुटपाथ पर किए गए अवैध अतिक्रमण के संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी दीपक सिंहनवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देश पर आहूत की गई।

बैठक में जल निगम, नगर पालिका परिषद लोनी, लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया। जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि पावी पुस्ता से बलराम नगर तक करीब 2800 मीटर सीवर लाइन डाली जानी है, जिसमें से 2500 मीटर कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 300 मीटर कार्य शेष है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिल्ली बॉर्डर से पावी पुस्ता तक पुराने 709बी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली से पावी की ओर बलराम नगर तक अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पावी से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में लोनी बस डिपो से बॉर्डर तक निर्माण कार्य जारी है। बैठक के बाद उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शेष 300 मीटर सीवर लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराने, फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाने और निर्माण कार्यों के दौरान निकली रेत व मिट्टी को ढककर रखने के निर्देश दिए। साथ ही धूल प्रदूषण रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने तथा आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधिकारियों ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध केशव कुमार चौधरी ने अपने कार्यालय में शिकायत लेकर आए लोगों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने भी अपने कार्यालय में आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच कर जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/ यातायात राजकरन नैय्यर ने भी अपने कार्यालय में शिकायत लेकर आए व्यक्तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आमजन की शिकायतों का शीघ्र समाधान पुलिस की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ब्राह्मणों के बाद अब जाट और गुर्जरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राजकुमार भाटी का लगातार हो रहा विरोध

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। नेताओं के बिगड़े बोल और विवादित बयान अक्सर राजनीति और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दिए गए ऐसे बयानों पर अक्सर भारी विरोध और राजनीतिक घमासान मच जाता है। अक्सर देखा गया हैं कि कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे बयान देते हैं जो समाज में कटुता या तनाव का कारण बन सकते हैं। ऐसा ही एक मामला गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा का हैं जहाँ सपा के विवादित प्रवक्ता राजकुमार भाटी सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में ऊटपटांग बोलते नजर आ रहे हैं। पहले ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद अपनी फजीहत करवा चुके भाटी अब जाट और गुर्जर समाज की पारिवारिक व्यवस्था को लेकर एक बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। इस बयान के सामने आते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। जहां जाट और गुर्जर समाज के लोगों में सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भाटी के माफी मांगने के बाद भी यह मामला थमने की जगह लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अंदर खाने उनसे नाराज चल रहे है। इसी मामले में अब तक गौतमबुद्ध नगर जिला बार

एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष मनोज भाटी एवं सचिव सचिव शोभाराम चंदीला ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनके साथ ही सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस घटनाक्रम ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र दुबे ने कहा कि प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होता है। प्रवक्ता का एक गलत वक्तव्य पार्टी का नुकसान करता है। हमारी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मणों पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग ली है इसलिए इस प्रकरण को और तूल ना दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि आगे से वह ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ निर्देश है कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जिससे किसी समुदाय का अपमान हो। वही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने कहा कि राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण, गुर्जर एवं जाट समाज को लेकर दिए गए तथाकथित बयान से तीनों समाजों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस प्रकार की बयानबाजी सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे के लिए उचित नहीं है। सभी समाजों का सम्मान बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसे शब्दों एवं टिप्पणियों से बचना चाहिए जिनसे समाजों के बीच परस्पर कटुता, वैमनस्य या तनाव उत्पन्न हो। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो तथा सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संयमित एवं मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए, यही समाजहित में उचित होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को आरक्षण पत्र निर्गत किए गये

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने किसानों के हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेक्टर 29 के तिरथली गाँव के किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने के लिए आरक्षण पत्र निर्गत कर दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अपने हाथों से कृषक वीरेंद्र कुमार को उनका आरक्षण पत्र प्रदान किया। साथ ही 588 अन्य किसानो के आरक्षण पत्र भूलेख विभाग द्वारा डाक से प्रेषित किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 29 में अपरेल पार्क के विकास में अहम पहल करते हुए समस्त किसानो के आरक्षण पत्र निर्गत किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही इन सभी भूखंडों को विकसित करते हुए किसानों को भौतिक कब्जा भी प्रदान किया जायेगा।

लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स एवं बीकमिंग बेटर का ऑनलाइन सत्र आयोजित

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। देश के छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करने और उनकी संचार और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन सत्र (जूम मीटिंग द्वारा) लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स एवं बीकमिंग बेटर हर माह आयोजित किया जाता है। लर्निंग फ्रॉम लीजेंड श्रृंखला सत्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करना और दूसरा उन्हें इस मंच पर बोलने का अवसर देना ताकि उनके सार्वजनिक भाषण कौशल को निखारा जा सके। बीकमिंग बेटर सत्र का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस बार बीकमिंग बेटर श्रृंखला के अंतर्गत 'ना कहना सीखो' 'पर चर्चा की गई। जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खरे की अध्यक्षता में विभिन्न शहरों से आठ चुने हुए विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन वैंपल्ली नसरीन ने किया। वे एमआईटीएस मदनापल्ले (आंध्र प्रदेश) में एमसीए की छात्रा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब के चुनिंदा विद्यार्थियों ने वक्ता के रूप में भाग लिया। सत्र के सबसे प्रभावशाली वक्ता पहल शर्मा को चुना गया, जो दयानंद मॉडल स्कूल जालंधर (पंजाब) की 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। इनको मुकेश भटनागर द्वारा रबानी जौली लिखित पुस्तक 'भविष्य की नींव' भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन सभी वक्ताओं को भागीदारी के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र देकर किया गया।

ओएसडी के फर्जी हस्ताक्षर से जारी लोन के लिए बनाया मॉर्गेज पत्र

नोएडा। सेक्टर-18 में दुकान पर लोन लेने के लिए प्राधिकरण के ओएसडी के फर्जी हस्ताक्षर कर जारी जाली मॉर्गेज (बंधक) पत्र सामने आया है। पत्र को सेक्टर-62 स्थित बैंक की शाखा में लोन के लिए जमा भी कर दिया गया था। बैंक से परीक्षण के लिए पत्र जब प्राधिकरण पहुंचा तब इसका खुलासा हुआ। जे-ब्लॉक स्थित दुकान के आवंटी ने करीब दो महीने पहले लोन के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया था। प्लॉट का मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इस पर विधि विभाग से राय मांगी गई थी। कोर्ट केस का हवाला देते हुए विधि विभाग ने मॉर्गेज पत्र जारी न करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जालसाज ने 14 मई 2026 की तारीख में फर्जी मॉर्गेज पत्र तैयार कर लिया और इस पर प्राधिकरण के ओएसडी अशोक शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर कर दिया गया।

बढ़ती गर्मी में बढ़ा टाइफाइड का खतरा, दूषित पानी और खानपान बन रहा वजह

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा है। इनमें टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है, जो हर साल हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेती है। तेज गर्मी, दूषित पानी, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और साफ-सफाई की कमी इस बीमारी के फैलने के प्रमुख कारण हैं। इसलिए सावधानी जरुरी है। फेलिक्स हॉस्पिटल की डॉ प्रियंका सिंह, जनरल फिजिशियन ने बताया कि गर्मी के मौसम में टाइफाइड के मामले सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सामने आते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है।टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति के मल या मूत्र से बैक्टीरिया पानी और खाने में पहुंच जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, कटे फल, बर्फ और दूषित पेय पदार्थ भी संक्रमण का कारण बनते हैं। टाइफाइड मुख्य रुप से दो प्रकार का माना जाता है। पहला टाइफाइड फीवर, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, जबकि दूसरा पैराटाइफाइड, जो साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। पैराटाइफाइड के लक्षण अपेक्षाकृत हल्के हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में टाइफाइड अब भी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है।भारत में हर साल लाखों लोग टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष लगभग 90 लाख से अधिक टाइफाइड के मामले सामने आते हैं और इनमें बड़ी संख्या भारत जैसे विकासशील देशों की होती है। स्वच्छ पेयजल और बेहतर सैनिटेशन की कमी इसके प्रसार का बड़ा कारण है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी दूषित पानी और खुले में शौच जैसी समस्याएं बीमारी को बढ़ावा देती हैं। गर्मियों में पानी की कमी होने पर लोग कई बार असुरक्षित स्त्रोतों का पानी पीने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

ट्रैफिक की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक, पुलिस उपायुक्त से मिले किसान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक भाटी के नेतृत्व में पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक गौतम बुध नगर अभय मिश्रा के साथ ट्रैफिक पुलिस से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ग्रामीणों एवं किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्रामों के बाहर खड़ी गाड़ियों को अवैध पार्किंग बताकर चालान काटे जा रहे हैं तथा वाहन टो कर छोड़ने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों के बाहर खड़े वाहनों को अवैध ढंग से उठाया जाता है और किसानों को अनावश्यक परेशान किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक्टर एवं अन्य किसान यंत्रों को चौराहों पर रोककर चालान एवं वाहन सीज करने की धमकी देकर अवैध उगाही की जा रही है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई ग्रामों के बाहर रोड कट बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाकियू पदाधिकारियों ने सेक्टर-81 मेट्रो स्टेशन के पास सैमसंग कट, मेट्रो स्टेशन-101, हनुमान मंदिर बरौला के सामने तथा एनईपीजेड चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हो रही अवैध उगाही पर विरोध जताया। बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि एनईपीजेड चौराहे सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रॉन्ग साइड के नाम पर राहगीरों एवं ग्रामवासियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही युवाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर पैसे न देने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। अशोक भाटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमानी से बाज आए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस पर नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक गौतम बुद्ध नगर अभय मिश्रा ने सभी समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई एवं इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। बैठक के दौरान संबंधित समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह, एनसीआर अध्यक्ष परविंदर अवाना, दादरी जिला अध्यक्ष मनोज मावी, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप भाटी, जिला उपाध्यक्ष अनिल खारी, सिंह राज गुर्जर, सचिन अवाना, गजेंद्र रेक्सवाल, कृष्ण भाटी, कमलजीत खारी, शैलेश बेसोया, तरुण बेसोया, सोनू यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

ग्रेनो के साप्ताहिक बाजार शिफ्ट होंगे

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के साप्ताहिक बाजार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण योजना पर काम कर रहा है। इसे लेकर एक सर्वे भी कराया जाएगा। प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग को सीईओ एनजी रवि कुमार ने इस पर काम करने के लिए कहा है।

अभी सेक्टर डेल्टा-1 में सोमवार और बृहस्पतिवार, गामा-1 में शनिवार और बीटा-2 में रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। इसी तरह ग्रेनो वेस्ट में भी सोसाइटियों के बाहर साप्ताहिक और नियमित बाजार सड़कों पर ही लगते हैं। ज्यादा समस्या ग्रेनो वेस्ट इलाके में है। सीईओ ने बताया कि इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि जाम जैसी स्थितियों से लोगों को परेशानी न हो। इन्हें तय स्थान से आसपास ही शिफ्ट किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज की अनूठी पहल

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भारत सरकार के विशेष दिशा-निदेशों के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारीज द्वारा नोएडा के सेक्टर-52 केंद्र पर एक विशेष जागरूकता और प्रेरणादायक सत्र का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष देश भर में वरिष्ठ नागरिकों में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा फूंकने के लिए सरकार ने ब्रह्माकुमारीज को अधिकृत किया है। इसी कड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस विशेष सत्र की मुख्य वक्ता नोएडा क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं की प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी लीना दीदी रहीं। पिछले 38 वर्षों से मानवता और समाज सेवा में समर्पित लीना दीदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धावस्था जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों का अनमोल खजाना है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण बुजुर्गों के मार्गदर्शन के बिना अधूरा है। उन्होंने समाज में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, उनके सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। दीदी ने बताया कि कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक जागृति से उम्र के इस पड़ाव को भी उत्सव में बदला जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनके समाज के प्रति अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ जन ने माना कि ऐसे आयोजन उन्हें समाज में अपनी उपयोगिता का अहसास कराते हैं। अंत में, संस्था के सेवा प्रभाग द्वारा सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सभी के लिए पवित्र और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस आत्मीयता से भरे वातावरण ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

कांग्रेस कमेटी नें किया सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन

पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी के दामों में वृद्धि पर दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा द्वारा अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय सैक्टर 19 पर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महाहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सौंपा गया। प्रवक्ता पवन शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में की जा रही लगातार वृद्धि से घरेलू उपयोग की सभी वस्तुओं की लागतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करती है कि जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को तुरंत बढ़े हुए दामों को वापस लेने के लिए निर्देशित करे अन्यथा कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बन कर संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर, प्रवक्ता पवन शर्मा, वरिष्ठ नेता फिरे सिंह नागर, राजकुमार भारती, ललित अवाना, संजय तनेजा, राजकुमार त्यागी, रामकुमार शर्मा, राहुल पांडेय, डॉ सीमा, विक्रम चौधरी, सुल्तान सिंह बिधूड़ी, दयाशंकर पांडेय, शिवानी पंवार, वीरेंद्र सिंह, मनोज तिवारी, भव्य रावत, श्याम सिंह चौहान, विश्वनाथ शास्त्री, सतीश एवं अरुण प्रधान सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए।

लखनऊ के ध्यानार्थ आज मंत्री करेंगे प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा

नोएडा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंगलवार को लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। यह बैठक मुख्य रूप से 20 बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसकी तैयारी में सोमवार को पूरा दिन प्राधिकरण के अधिकारी जुटे रहे। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, दोनों एसीईओ वंदना त्रिपाठी एवं सतीश पाल और वित्त नियंत्रक सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट तथा प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए परियोजनाओं की स्थिति, पिछले दो वर्षों में किए गए आवंटन और 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकायेदारों की विभागवार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर प्रभावी जीरो पीरियड पॉलिसी में हुई फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की प्रगति भी देखी जाएगी।

सांसद डॉ महेश शर्मा एवं विधायक पंकज सिंह ने किया आरडब्लूए सेक्टर 53 के गेट का उद्घाटन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। सांसद डॉ महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह नें संयुक्त रूप से आरडब्लूए सेक्टर 53 के गेट नंबर 3 का उ द्घाटन किया। आरडब्लूए अध्यक्ष बालेश मित्तल ने बताया कि सेक्टर वासियों की मांग पर सेक्टर में प्रवेश हेतु गेट नंबर 3 पर एक भव्य प्रवेश द्वारा बनाया गया है जिसका सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने आज संयुक्त रूप से उ द्घाटन किया। सांसद डॉ महेश शर्मा ने आरडब्लूए अध्यक्ष बालेश मित्तल की तारीफ करते हुए कहा की सुरक्षा की दृष्टि से गेट का निर्माण अति आवश्यक है, आरडब्लूए की टीम नें बहुत सी सराहनीय कार्य किया है। मंच का संचालन प्रमुख समाजसेवी एवं हरियाणा वैश्य समाज सेवा के अध्यक्ष धर्मपाल गोयल ने किया। इस अवसर पर डी पी गोयल, डीडी आरडब्लूए अध्यक्ष एन पी सिंह, फोनरवा महासचिव के के जैन, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, भाजपा महामंत्री अमित त्यागी, सत्यनारायण गोयल, उपदेश भारद्वाज, सर्वजीत सिंह, रणधीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, परमजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। वही उ द्घाटन समारोह में आरडब्लूए से अध्यक्ष बालेश मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, उपाध्यक्ष हितेन्दर शर्मा, महासचिव वीरेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव विद्या शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह मनराल, सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल, इंदर मोहन, आलोक जैन, सर्वजीत सिंह, राजीव गुप्ता तथा समस्त सेक्टर वासियों ने हिस्सा लिया।

सम्पादकीय

ट्रंप की नीति पर सवाल

दुनिया इस समय कई बड़े संकटों के दौर से गुजर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और युद्ध की स्थितियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में विश्व के कई नेता लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हालात नहीं बदले तो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में एक अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा कि वर्तमान समय आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। उनका कहना था कि यदि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध नहीं रुका तो दशकों में हासिल की गई आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां खतरे में पड़ सकती हैं। इससे दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी की ओर धकेली जा सकती है। इसी तरह लॉरेंस वोंग ने भी चेतावनी दी है कि बढ़ता ऊर्जा संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी की ओर ले जा सकता है। फारस की खाड़ी का अहम मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी तनाव के घेरे में है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा तो तेल और गैस की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे विकसित देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इन देशों की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर युद्ध का सीधा प्रभाव पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक संकट के बावजूद उनकी विदेश नीति टकराव को और बढ़ाने वाली दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि ट्रंप का हालिया दौरा चीन के साथ कोई बड़ा समझौता कराने में सफल नहीं रहा। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर सख्त रुख दोहराया। इस बीच ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई सैन्य रणनीति पर विचार कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। उधर वैश्विक बाजारों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। कई देशों को अपने रणनीतिक तेल भंडार खोलने पड़े हैं। ऊर्जा कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का असर खाद और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भी पड़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा चला तो दुनिया भर में करोड़ों लोग खाद्य संकट और भुखमरी के जोखिम में आ सकते हैं। भारत में भी इस संकट के प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। देश में गिग वर्कर्स और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

दैनिक राशिफल

मेष : चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।
दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी में संतोष रहेगा। निवेश शुभ रहेगा।

वृषभ : इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। निवेश मनोनुकूल लाभ देगा।

मिथुन : का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा।
परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। तनाव रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है।

कर्क : ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।
बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। व्यापार मनोनुकूल चलेगा। नौकरी में चैन रहेगा।

सिंह : मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।
धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी। नई योजना बनेगी। तत्काल लाभ नहीं होगा। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

कन्या : टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो।
व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेंगे। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा। लंबित कार्य पूर्ण होंगे।

तुला : रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।
व्यवसाय ठीक चलेगा। पुराना रोग उभर सकता है। दूर से दु:खद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी।

वृश्चिक : तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।
जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। निवेश में जल्दबाजी न करें। नौकरी में शांति रहेगी।

धनु : तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।
भूमि व भवन इत्यादि की खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी।

मकर : भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।
विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

कुंभ : गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।
किसी अपने ही व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। थकान व कमजोरी रह सकती है। स्वास्थ्य पर खर्च होगा।

मीन : दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।
धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
RNI No. : UPHIN/2022/84480
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म, नई दिल्ली
मो. नं.: +91 99990 74369
ओमीलाल वर्मा (एडवोकेट)
मो. नं.: 98109 03664

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road, Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

महंगाई से आम आदमी की जेब ढीली

डा. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक भूराजनीतिक चुनौतियों के बीच देश में महंगाई बढ़ने की चुनौती उभरकर दिखाई दे रही है। हाल ही में 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अप्रैल 2026 में थोक महंगाई बढकर 8.3 प्रतिशत और खुदरा महंगाई बढकर 3.48 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह महंगाई से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी भारत में महंगाई बढ़ने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार धीमी हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। ऐसे में पश्चिम एशियाई संकट के कारण नागरिकों को यह जिम्मेदारी निभानी होगी कि वे जहां तक संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक कारों और कार पूलिंग को प्राथमिकता दें। साथ ही कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दें। देश और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ भी भारत को पश्चिम एशिया संकट के झटकों और वैश्विक अनिश्चितता के लिए खुद को तैयार रखने संबंधी टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 मई को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गर्वनर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई का दबाव बढ़ने पर अब नीतिगत रीपो रेट में वृद्धि की कार्रवाई की जानी होगी। गौरतलब है कि इन दिनों पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से भारत में महंगाई बढ़ने लगी है। उल्लेखनीय है कि 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ एक मई से 19 किलोग्राम के वाणिज्यक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए और 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 549 रुपए की बढ़ोतरी का असर रेस्टोरेंट, ढाबों और रोजमर्रा के काम में एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले व्यवसायों की लागत बढ़ने के रूप में दिखाई देने लगा है। इस बड़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर होने से महंगाई बढ़ने लगी है। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों इंडियन आयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को संयुक्त तौर पर हर माह करीब 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तेजी से दुनिया के विभिन्न

देशों में महंगाई बढ़ रही है, उसकी तुलना में भारत में महंगाई बढ़ने की दर कम है, लेकिन महंगाई बढ़ने की प्रवृत्ति उभरकर दिखाई दे रही है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा 10 मई को प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 2026 में भारत में महंगाई 6.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है। इसी तरह प्रमुख कंसल्टेसी फर्म ईवाई इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशियाई संकट के कारण भारत में वित्त वर्ष 2026-27 में महंगाई दर 6 प्रतिशत के ऊपरी स्तर को छू सकती है। उल्लेखनीय है कि 8 मई को क्रिसिल के द्वारा प्रकाशित ताजा 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में घर पर बनी शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत बढ़ गई है। देश में आम आदमी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरण आदि महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय देश में दैनिक जरूरतों के समान बनाने वाली कई फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियां अपने उत्पादों कीमत बढ़ाने या पैकेट के वजन घटाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

इतना ही नहीं, देश में महंगाई बढ़ने की एक नई चिंता यह भी है कि भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि सरकार देश के आम आदमी को पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगाई से बचाने के मद्देनजर रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी है। इसके मद्देनजर पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए उत्पाद कर में 10 रुपए प्रतिलीटर की कटौती की गई ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सकेगा। सरकार ने निर्यात किए जाने वाले डीजल और हवाई ईंधन (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क 34 रुपए बढ़ा दिया है, ताकि देश में ईंधन की कमी ना हो और कीमतें काबू में रहें। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया है। देश की सभी तेल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। बाजार में पेट्रोल और डीजल की बाजार में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जा रही है। रोजाना करीब 50 लाख गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग 97 प्रतिशत है। सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने तथा आम आदमी पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के मद्देनजर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए खाद्यान्न की रणनीतिक बिक्री करने और जरूरी आयात की सुविधा जैसे कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि पश्चिम एशिया संकट से निर्मित महंगाई की चुनौती के बीच कुछ अहम बुनियादी बातें भारत के लिए महंगाई नियंत्रण की शक्ति बन गई हैं। सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के लिए की गई विभिन्न आर्थिक और कूटनीतिक पहलों के लाभ मिले हैं। इस समय भारत के पास विशाल खाद्यान्न भंडार आर्थिक अनुकूलता के रूप में दिखाई दे रहा हैं। देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में अप्रैल 2026 के अंत तक लगभग गेहूं और चावल का 6.02 करोड़ टन से अधिक का उपलब्ध स्टॉक खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की मजबूती है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

इतना ही नहीं महंगाई की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 690 अरब डॉलर का संचय है। चूंकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, अतएव सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। देश के नागरिकों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई उस अपील पर अमल किया जाना होगा जिसमें उन्होंने पेट्रोल-डीजल का किफायत से उपयोग करने की जरूरत बताई है। उम्मीद करें कि सरकार के द्वारा पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगाई नियंत्रण के मद्देनजर ब्राजील रूस और वेनेजुएला से लाभप्रद दिखाई दे रहे कच्चे तेल का अधिक आयात किया जाएगा। पेट्रोल में इथेनाल का मिश्रण 30 प्रतिशत किया जाएगा। तेल की मांग में कमी करने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के उपयोग में तेजी लाई जाएगी। सरकार के द्वारा गैर विकास कार्यों पर खर्च में कमी के साथ अनावश्यक सब्सिडी में कटौती की जाएगी। सरकार के द्वारा खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी सहित उर्वरकों की उपयुक्त आपूर्ति के लिए आगे बढ़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा के कूटनीतिक निहितार्थ भारत के लिए महत्वपूर्ण

कमलेश पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के हालिया विदेश दौरे के कई बड़े कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि मई 2026 में उनका यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया ऊर्जा संकट, ईरान युद्ध, सप्लाई चेन अस्थिरता और नए वैश्विक ध्रुवीकरण से गुजर रही है। लिहाजा, पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।

पहला, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक देश है। ईरान संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यूएई दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। लिहाजा भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी सप्लाई, ऊर्जा निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे अहम समझौते हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत भविष्य के किसी बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए खुद को सुरक्षित करना चाहता है।

दूसरा, पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ बढ़ रही है, क्योंकि यूएई ने पीएम मोदी का असाधारण स्वागत किया- एफ-16 एस्कॉर्ट और राष्ट्रपति स्तर की अगवानी- यह दिखाता है कि भारत अब केवल 'तेल खरीदने वाला देश' नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। इसके मायने ये निकलते हैं कि पाकिस्तान की पारंपरिक खाड़ी पकड़ कमजोर होगी और भारत की अरब देशों में स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। इससे रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार भी होगा।

तीसरा, यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारी विकसित होगी, क्योंकि नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का चयन बहुत रणनीतिक माना जा रहा है। चूंकि इन देशों से भारत सेमीकंडक्टर

तकनीक, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई और रक्षा तकनीक और आर्कटिक एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहता है। विशेषकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए इस पहल के अपने रणनीतिक मायने हैं।

चौथा, चीन और अमेरिका दोनों को संतुलित संदेश देने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा 'मल्टी-अलाइनमेंट' नीति का हिस्सा भी है, इससे अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से संबंध, अरब देशों से सामरिक निकटता, यूरोप के साथ तकनीकी सहयोग, चीन के प्रभाव का संतुलन बढ़ेगा। चूंकि भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है।

पांचवां, भारत को निवेश हब बनाने की कोशिश यूएई द्वारा भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है। यह 'मेक इन इंडिया' और 'भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने की रणनीति से जुड़ा है।

छठा, घरेलू राजनीति के संकेत के नजरिए से दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से ईंधन बचाने, विदेशी यात्राएं कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद बड़े वैश्विक दौरे कर रहे हैं। इसका राजनीतिक संदेश यह जाएगा कि कठिन वैश्विक समय में सक्रिय नेतृत्व पीएम दे रहे हैं और भारत संकट में भी वैश्विक केंद्र बना हुआ है। इससे पीएम मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि मजबूत होकर चमकेगी।

सातवां, भारत की वैश्विक छवि निर्माण के दृष्टिकोण से यह दौरा यह दिखाने का प्रयास भी है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा, तकनीक, व्यापार और सुरक्षा में निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। विशेषकर जी20 के बाद भारत अपनी 'विश्व नेतृत्व' छवि को स्थायी बनाना चाहता है। इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभाव भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे जहां ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना रहेगी।

साथ ही रक्षा-तकनीकी सहयोग विस्तार से वैश्विक प्रभाव में वृद्धि होगी। भारत की यह नई चाल चीन के लिए यूरोप और खाड़ी में भारत की सक्रियता चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। जबकि पाकिस्तान के लिए खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता रणनीतिक दबाव बढ़ा सकती है। वहीं, यूरोप के लिए चीन के विकल्प के रूप में भारत की अहमियत बढ़ेगी। जबकि अमेरिका के लिए भारत एक आवश्यक रणनीतिक साझेदार बना रहेगा, भले ही वह पूरी तरह अमेरिकी धड़े में न जाए।

निष्कर्ष यह निकलता है कि पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।

बच्चों को अवसाद के दुष्चक्र में धकेलता सीबीएसई का कार्पोरेट मॉडल

अंजनी सक्सेना

भारत का परीक्षा तंत्र आज जिस दौर से गुजर रहा है, उसे यदि केवल लापरवाह या अक्षम कह दिया जाए, तो यह इस तंत्र के असली और क्रूर चरित्र को छुपाने जैसा होगा। सच तो यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का निष्ठुर, संवेदनहीन चेहरा इस वर्ष देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र आज एक ऐसे अनवरत और सुनियोजित अवसाद के दुष्चक्र में फंसे हैं, जहाँ से निकलने का हर रास्ता बंद दिखाई देता है। यह अवसाद तीन स्तरों पर छात्रों और उनके अभिभावकों को लील रहा है। पहले देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक और उसमें हुई ऐतिहासिक धांधली ने साल भर रात-दिन एक करने वाले बच्चों के भरोसे को सरेबाजार नीलाम कर दिया। बच्चे अभी इस सदमे से संभल भी नहीं पाए थे कि सीबीएसई की 12 वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में अपनाई गई अप्रत्याशित और मशीनी कठोरता ने लाखों होनहार छात्रों को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया। इसके बाद, जब अपनी न्यायसंगत मांग और अंकों में सुधार की आखिरी उम्मीद लेकर छात्र सीबीएसई के पास पहुँचे, तो बोर्ड ने 'री-चेकिंग' (पुनर्मूल्यांकन) के नाम पर फीस का एक ऐसा सामंती और कॉर्पोरेट जाल बिछा दिया, जिसने शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की ही हत्या कर दी। यह त्रि-स्तरीय मार पहले पेपर लीक फिर कठोर मूल्यांकन और अंत में री-चेकिंग के नाम पर मोटी रकम की वसूली, भारतीय शिक्षा तंत्र के ऐसे व्यावसायिक अंधेपन को दशार्ती है, जिसने आज गरीब और अमीर के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया है।

इस वर्ष सीबीएसई ने बड़े जोर-शोर और ढोल-नगाड़ों के साथ अपनी मूल्यांकन प्रणाली में आधुनिकता का समावेश करते हुए डिजिटल चेकिंग यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया। बोर्ड का दावा था कि इस तकनीक से मानवीय गलतियां न्यूनतम होंगी, पारदर्शिता आएगी और परिणाम अधिक सटीक व त्वरित होंगे लेकिन धरातल पर इस मशीनी और निष्ठुर चेकिंग प्रक्रिया का असर बेहद खौफनाक और आत्मघाती रहा। डिजिटल स्क्रीन पर लगातार कॉपियां देखते-देखते परीक्षकों की मानवीय संवेदना और छात्रों के प्रति सहानुभूति पूरी तरह समाप्त हो गई। इस प्रणाली के तहत परीक्षकों पर एक निश्चित समय सीमा में दर्जनों कॉपियां जांचने का प्रशासनिक दबाव था, जिसके कारण उन्होंने उत्तरों की गहराई, छात्र की मौलिक सोच और तार्किकता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। बोर्ड द्वारा प्रदान की गई एक रूखी आंसर की को अंतिम सत्य मानकर कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल पेन चलाए गए। यदि छात्र का उत्तर शब्दशः उस कुंजी से मेल नहीं खाता था, तो उसे शून्य या बेहद कम अंक दिए गए। इस यांत्रिक और संवेदनहीन मूल्यांकन का परिणाम यह हुआ कि जिन बच्चों को अपने साल भर के बेहतरीन प्रदर्शन और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर 90 से 95% अंकों की उम्मीद थी, वे 70% से 75% के बीच सिमट कर रह गए और 75 से 90 प्रतिशत की उम्मीद

वाले 60 से 65 प्रतिशत पर ही अटका दिए गए। अंकों में आई यह अप्रत्याशित गिरावट केवल एक संख्यात्मक विफलता नहीं है, इसने छात्रों के करियर के सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। भारत के उच्च शिक्षा ढांचे में, विशेषकर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में, 12 वीं कक्षा के अंक केवल एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि पात्रता की पहली अनिवार्य शर्त हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आई टी (क्क्क्ळ) में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड की परीक्षा पास करने के साथ-साथ 12 वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही अनेक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सीएलसी राउंड में प्रवेश भी 12वीं के अंको के आधार पर प्रवेश देते हैं।

अब सीबीएसई की इस कठोर और त्रुटिपूर्ण डिजिटल चेकिंग के कारण हजारों ऐसे होनहार छात्र, जो जेईई मेंस और एडवांस्ड की कट-ऑफ को आसानी से पार करने की क्षमता रखते हैं, बोर्ड में 75% के इस जादुई आंकड़े से चूक गए। इसके कारण वे देश के शीर्ष कॉलेजों में एडमिशन की रेस से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। कहने को तो सीबीएसई ने एक विषय में सुधार परीक्षा देने के विकल्प रखा है लेकिन एक विषय की परीक्षा देकर5 से 10 प्रतिशत अंको का अंतर पूरा करना मुश्किल है। यह सीधे तौर पर उन मेधावी बच्चों के भविष्य पर हमेशा के लिए ताला लगाने जैसा है जिन्होंने दो-तीन साल तक कड़े परिश्रम के साथ देश के सबसे कठिन एग्जाम की तैयारी की थी, और अब व्यवस्था की इस तकनीकी चूक के कारण उनका पूरा साल और करियर बर्बाद होने की कगार पर है।

जब परिणाम घोषित हुए और देश भर के लाखों छात्रों ने देखा कि उनके अंक उनकी वास्तविक मेहनत और अपेक्षा से बहुत कम हैं, तो उनके भीतर व्यवस्था से न्याय पाने की एक उम्मीद जागी। वे छात्र चाहे अमीर घर के हों, मध्यमवर्गीय परिवार के हों, या किसी गरीब दिहाड़ी मजदूर के होनहार बच्चे, सभी को लगा कि सीबीएसई का री-चेकिंग सिस्टम उनकी कॉपियों के साथ न्याय करेगा। लेकिन सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया तैयार की है, वह वास्तव में किसी लोककल्याणकारी बोर्ड की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेट कंपनी का राजस्व मॉडल दिखाई देती है। छात्रों और अभिभावकों की लाचारी का फायदा उठाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को तीन अत्यंत जटिल और महंगे चरणों में बांट दिया गया है, जिसे पार करना किसी भी आम परिवार के लिए वित्तीय रूप से असंभव बना दिया गया है। इस व्यवस्था में कोई भी छात्र सीधे अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन नहीं करवा सकता। उसे इस पूरे चक्रव्यूह से चरणबद्ध तरीके से गुजरना ही पड़ता है।

इस शुरूआती चरण में छात्र को केवल इस बात के लिए प्रति विषय 500 रुपए की राशि का भुगतान करना होता है कि कंप्यूटर या परीक्षक ने अंकों को जोड़ने में कोई गलती तो नहीं की। इस प्रक्रिया में उत्तरों को दोबारा नहीं जांचा जाता, सिर्फ टोटलिंग री-चेक की जाती है। सोचिए, जिस टोटलिंग को करने में आज के युग में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, उस महज एक क्लिक की प्रक्रिया के लिए छात्रों से करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं। यदि छात्र पहले चरण की फीस की औपचारिकता पूरी कर लेता है, तभी वह अपनी जांची गई कॉपी को देखने के लिए पात्र होता है।

इसके लिए उसे प्रति विषय फिर से 700 रुपए की अतिरिक्त फीस देनी पड़ती है। यानी, जो परीक्षा छात्र ने खुद दी है, जो उत्तर उसने साल भर अपने खून-पसीने से लिखे हैं, अपनी ही उस कृति को केवल एक पीडीएफ या डिजिटल फोटोकॉपी के रूप में देखने के लिए उसे बोर्ड की तिजोरी भरनी पड़ती है, जबकि इस बार के चैकिंग पैटर्न में पीडीएफ पहले से ही उपलब्ध है।

अपनी कॉपी की फोटोकॉपी मिलने के बाद, यदि छात्र को किसी शिक्षक या विशेषज्ञ की मदद से यह पता चलता है कि परीक्षक ने किसी प्रश्न को पूरी तरह गलत जांचा है या सही उत्तर पर भी कम नंबर दिए हैं, तब वह असली पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ खेल और भी अधिक क्रूर हो जाता है। यहाँ पूरी कॉपी दोबारा नहीं जांची जाती, यहां छात्र को प्रति प्रश्न (पर क्वेश्चन) 100 रुपए का अलग से भुगतान करना होता है। यदि किसी छात्र को गणित, भौतिकी या अर्थशास्त्र जैसे विषयों में 10 प्रश्नों पर आपत्ति है, तो उसे सिर्फ एक विषय के लिए 1000 रुपए अलग से देने होंगे। इस त्रि-स्तरीय लूट तंत्र को अगर गणितीय रूप से समझा जाए, तो एक छात्र को अगर अपने केवल तीन मुख्य विषयों (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) की कॉपियों को पूरी तरह चुनौती देनी हो, तो उसका कुल खर्च पांच हजार से लेकर आठ हजार के बीच बैठता है। क्या एक आम भारतीय परिवार के लिए, यह रकम मामूली है?

यहाँ आकर यह व्यवस्था अमीर और गरीब के बीच एक स्पष्ट और खतरनाक विभाजन पैदा कर देती है। एक संपन्न परिवार का बच्चा, अगर उसके नंबर कम आते हैं, तो उसके माता-पिता बिना सोचे-समझे हजारों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और री-चेकिंग के तीनों चरणों को पार कर लेते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि री-चेकिंग के बाद बच्चों के 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं, जो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य शीर्ष कॉलेजों की कट-ऑफ लिस्ट में शामिल करवा देते हैं।

सीएम डैशबोर्ड: जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों की समीक्षा

समय सीमा में पूरे हों निर्माण कार्य, अधूरे आवास जल्द पूर्ण कराने के निर्देश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में नवीन व्यवस्था के अंतर्गत सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि योजना के निर्धारित लक्ष्यों का शत-प्रतिशत निस्तारण बैंकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिए कि जो आवास अभी अधूरे हैं, उनका निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में सैम और मैम बच्चों के चिन्हांकन तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्य की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण संबंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ऋण योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग एवं एलडीएम को निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों की पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण कर युवाओं को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ लगातार असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों, लाभार्थीपरक योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए। यदि किसी स्तर पर शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतपाल वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक जय राम सिंह, डीसी मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए एसके राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कचनरवा व करईल में लगेगा विशाल विद्युत मेगा कैम्प, उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

कोन/सोनभद्र। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के अंतर्गत पिपरी क्षेत्र के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र कचनरवा द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दो दिवसीय विशाल विद्युत मेगा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 20 मई 2026 को कचनरवा मार्केट स्थित बाबू पीसीओ परिसर में तथा 21 मई 2026 को करईल मार्केट के पंचायत भवन में मेगा कैम्प आयोजित होगा। अवर अभियंता ए.पी. गुप्ता ने बताया कि कैम्प का उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। कैम्प में नया घरेलू एवं कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन, नाम परिवर्तन, पता संशोधन, लोड वृद्धि, विधा परिवर्तन, बिजली बिल संशोधन, बिल भुगतान, खराब मीटर की जांच और बदलने सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के यहां अभी तक मीटर नहीं लगे हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। विद्युत संबंधी शिकायतों का पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अपडेट करने तथा केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। विभाग की ओर से बताया गया कि मेगा कैम्प में विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान कराया जा सके। विद्युत विभाग ने क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कैम्प का लाभ उठाएं और अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान कराएं।

विश्व हिंदू महासंघ संगठन में महामंडलेश्वर किरन नंदगिरी को बड़ी जिम्मेदारी: बनीं क्षेत्रीय महामंत्री

योगी सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएंगी किरन नंदगिरी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। विश्व हिंदू महासंघ संगठन द्वारा संगठन विस्तार अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी क्रम में महामंडलेश्वर किरन नंदगिरी को विश्व हिंदू महासंघ संगठन के किन्नर प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से संगठन के कार्यकताओं एवं समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल है। यह नियुक्ति विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति तथा किन्नर प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष काजल किरन की संस्तुति पर की गई। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि महामंडलेश्वर किरन नंदगिरी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए संगठन को नई मजबूती प्रदान करेंगी। नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री महामंडलेश्वर किरन नंदगिरी ने नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के विचारों और जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि समाज के अधिकारों, शिक्षा, सम्मान और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि विश्व हिंदू महासंघ संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गांव-गांव और शहर-शहर कार्यकताओं को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा, जिससे संगठन की आवाज को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। महामंडलेश्वर किरन नंदगिरी की नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकताओं एवं क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नीति आयोग की रैंकिंग में सोनभद्र बना देश का नंबर-1 आकांक्षी जिला

समग्र विकास में ऐतिहासिक उपलब्धि, स्वास्थ्य, कृषि एवं जनकल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मिला राष्ट्रीय सम्मान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद ने विकास की नई इबारत लिखते हुए पूरे देश में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जारी दिसंबर 2025 की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में सोनभद्र ने देश के 112 आकांक्षी जिलों को पीछे छोड़ते हुए समग्र विकास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि न केवल जनपद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र का ओवरऑल स्कोर नवंबर 2025 के 57.3603 से बढ़कर दिसंबर 2025 में 65.0066 पहुंच गया। जिले ने 7.646 का सर्वाधिक डेल्टा स्कोर अर्जित किया, जो देश के सभी आकांक्षी जिलों में सर्वोच्च रहा। यही ऐतिहासिक प्रदर्शन सोनभद्र को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान तक पहुंचाने का आधार बना। जनपद ने विशेष रूप से कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में जिले का स्कोर 37.9523 से बढ़कर 42.7207 हो गया तथा 4.768 अंकों का प्रभावी सुधार दर्ज किया गया। किसानों के हित में संचालित योजनाओं, जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास कार्यों का सकारात्मक प्रभाव इस उपलब्धि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी सोनभद्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में छठी रैंक हासिल की। जिले का स्वास्थ्य स्कोर 68.2721 से बढ़कर 86.4586 पहुंच गया, जो 18.187 अंकों की बड़ी वृद्धि को दशार्ता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, पोषण अभियानों के प्रभावी संचालन तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का यह परिणाम माना जा रहा है। हालांकि शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं आधारभूत संरचना जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन समग्र रूप से सोनभद्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति, सतत मॉनिटरिंग एवं जनसहभागिता के माध्यम से किसी भी जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता सोनभद्र की जनता, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हमारा प्रयास रहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पहुंचे। नीति आयोग की यह रैंकिंग जनपद के निरंतर विकास कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। आने वाले समय में शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ कार्य कर सोनभद्र को विकास के आदर्श मॉडल जनपद के रूप में स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि के लिए समस्त जनपदवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे सोनभद्र का सम्मान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनपद आने वाले समय में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा तथा देश के अन्य जिलों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगा।

ओबरा पुलिस ने अवैध गांजा के साथ युवक को दबोचा, डेढ़ किलो गांजा बरामद

एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज, आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना ओबरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलोग्राम 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपदभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा अमित कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ओबरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 की रात लगभग 10:36 बजे सेक्टर-04 पहाड़ी तिराहा के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने धीरज कुमार वर्मा पुत्र कपूर चंद वर्मा निवासी चूड़ी गली, मलीन बस्ती, ओबरा को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना ओबरा में मु0अ0सं0-111/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार को बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार गुप्ता तथा हेड कांस्टेबल संतोष कुमार पटेल शामिल रहे।

18 घंटे आपूर्ति का दावा पर 10-10 घंटे कट रही बिजली

नोएडा। मौसम जैसे-जैसे गर्म हो रहा है, वैसे-वैसे बिजली कटौती की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यमुना सिटी के रबूपुरा, दनकौर, बिलासपुर और जेवर में हर दिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा विभाग की ओर से किया जा रहा है। वास्तविकता में 10-10 घंटे बिजली कटौती के कारण लोगों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। विभाग की ओर से दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण रबूपुरा, जेवर, दनकौर और बिलासपुर में 6 घंटे बिजली कटौती की जाती है और हर दिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि तय शेड्यूल से भी 3-4 घंटे की ज्यादा कटौती हो रही है। साथ ही आपूर्ति होने पर भी लोगों को लो-वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी पूरे दिन ऐसे ही हालत बने रहे और लो-वोल्टेज के कारण पंखे कूलर रेंगते रहे। दोपहर में बार-बार ट्रिपिंग होने के कारण बिजली आती जाती रही।

मेधावियों को मेडल देकर किया गया सम्मानित

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

परसपुर/गोण्डा। मेधावियों का उत्साहवर्धन करने और अन्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सोमवार को परसपुर शिक्षाक्षेत्र के अंतर्गत प्योली स्थित जेपीएस शिक्षण संस्थान में परीक्षा परिणाम वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त सम्मान समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।

विद्यालय के संचालक शिखर पांडेय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अंक केवल एक संख्या नहीं हैं, बल्कि यह आपकी मेहनत और अनुशासन का प्रमाण हैं। असफलता से कभी न डरें, क्योंकि हर असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। छात्रों को अंकपत्र, स्टेशनरी किट व मेडल देकर सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा सम्मान समारोह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक छोटा सा प्रयास है। इस अवसर पर रामकुमार पांडेय, आरती सिंह, स्वाति सिंह, अवशेष गुप्ता, भवानीदीन, धर्मेंद्र तिवारी, बैजनाथ पांडेय आदि रहे।

अदिति सिंह ने जिले में टॉप कर किया नाम रोशन, किसानों ने दी बधाई

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। इंटरमीडिएट परीक्षा में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अदिति सिंह ने बुलंदशहर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। बता दे कि अदिति सिंह भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट ठाकुर विजय प्रताप सिंह की सुपुत्री हैं। अदिति की इस उपलब्धि पर भाकियू बलराज परिवार में हर्ष का माहौल है। आपको बता दे कि आज भाकियू बलराज के पदाधिकारियों ने अदिति सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें फूलों का बुके भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। भाकियू बलराज की राष्ट्रीय अध्यक्ष(महिला मोर्चा) रेखा सिवाल, प्रदेश अध्यक्ष योगेश वैष्णव सहित सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने अदिति को बधाई दी। इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल ने अदिति के माता-पिता को भी बधाई देते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि बेटी अदिति सिंह एक दिन जरुर समाज का नाम रोशन कर देश का नाम ऊंचा करेगी। अदिति जैसी बेटियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।बधाई देने वालों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन शर्मा, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष बृजेश भाटी, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री ब्रह्मचंद बैरागी, उत्तर प्रदेश महासचिव प्रशांत खारी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू खारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सोविंदर भाटी, मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र भाटी, जिला अध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर जोगिंदर पहलवान, बुलंदशहर जिला अध्यक्ष हेमंत पंडित आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अदिति सिंह की मेहनत और लगन की सराहना की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-58 और सेक्टर-63 क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। छिजारसी कॉलोनी में किराए पर रहने वाले हरदोई के राजन शर्मा(68) को शनिवार रात रामा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, घड़ौली, दिल्ली निवासी वसुदेव शर्मा(21) 14 मई की सुबह छोटी बहन मानसी को बाइक पर बैठाकर नोएडा के सेक्टर-62 स्थित संस्थान आ रहे थे। डी पार्क के पास उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वसुदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। मानसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सोमवार को इलाज के दौरान वसुदेव की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि वह ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई।

विकासखंड राजगढ़ के ब्लॉक सभागार में जनगणना प्रगणकों को जनगणना किट एवं नियुक्ति पत्र का किया गया वितरण

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

मिजार्पुर। विकासखंड राजगढ़ के ब्लॉक सभागार में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में तहसील मड़िहान विकासखंड राजगढ़ के मकान गणना हेतु नियुक्त 206 प्रगणको की बैठक दोपहर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राहुल मिश्रा नायब तहसीलदार मड़िहान ने किया। बैठक में आगामी 22 मई से 20 जून तक जनगणना 2027के प्रथम चरण में प्रत्येक गांव के प्रत्येक मजरे में होने वाले मकान गणना हेतु प्रत्येक प्रगणक को गणना किट जिसमें विभिन्न प्रकार के 11 सामग्री बैग एवं नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र वितरित किया गया। राजगढ़ में लगभग 190 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तहसील द्वारा निर्धारित हुआ है। जिसमें 206 प्रगणक पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जिनका विभिन्न एच एल बी ब्लाकों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य संपादित किया जाएगा। फरवरी 2027 से जातिगत जनगणना प्रारंभ होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित नायब तहसीलदार मड़िहान राहुल मिश्रा ने जनगणना कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपने आवंटित फील्ड में जाकर नजरी नक्शा का निर्माण कर ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्व गणना करा लें। उन्होंने कहा कि आपकी सुविधा के लिए अशोक कुमार सिंह, अभिषेक कुमार पटेल, अमित कुमार विश्वकर्मा की ड्यूटी फील्ड ट्रेनर के रूप में लगाया गया है। डिजिटल जनगणना में किसी भी प्रकार के असुविधा होने पर आप इनसे संपर्क करें। जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। अपने कार्य में सावधानी बरतें। खंड शिक्षा अधिकारी राजगढ़ संजय यादव ने ड्यूटी में लगे सभी अध्यापकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्ण ढंग से कार्य करने का सलाह दिया। कार्यक्रम में मड़िहान तहसील के कर्मचारी मनीष लेखपाल, धीरज शर्मा, सतीश कुमार सिंह नोडल, अध्यापक बटेश्वर सिंह, गीता सिंह, रविंद्र कुमार, दिनकर सिंह, रेखा सिंह, कृष्ण कुमार सिंह अनुदेशक विपिन सिंह संतोष पाठक, रमेश सोनी सहित सैकड़ो प्रगणक उपस्थित रहे।

योगी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, सभी पर लगी स्वीकृति की मुहर

ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग बनेगा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के निर्धारण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने ह्लउत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोगह्व के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए उनकी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का विस्तृत अध्ययन करेगा।

कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह आयोग गठित किया जा रहा है। आयोग प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगा और उसी आधार पर निकायवार आरक्षण की संस्तुति देगा। उन्होंने बताया कि आयोग सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की समकालीन एवं अनुभवजन्य जांच करेगा। इसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि पंचायतों में पिछड़े वर्गों की कितनी भागीदारी है, उनकी आबादी कितनी है और स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व किस स्तर तक मौजूद है। आयोग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पिछड़े वर्गों को पंचायत व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए पंचायतों में सभी वर्गों की संतुलित भागीदारी जरूरी है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू है। हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब आरक्षण तय करने से पहले समर्पित आयोग की रिपोर्ट आवश्यक हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण कुल पदों के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि किसी क्षेत्र में अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तो आयोग सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्र करेगा। आयोग पंचायतवार और निकायवार स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे। इनमें एक अध्यक्ष होंगे, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। बाकी सदस्यों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें पिछड़े वर्गों से जुड़े सामाजिक, प्रशासनिक और कानूनी विषयों का अनुभव हो। आयोग का कार्यकाल सामान्य रूप से छह माह का रखा गया है।

सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसी संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से यह आयोग गठित किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी पंचायत चुनावों से पहले लिया गया यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए आयोग की रिपोर्ट पंचायत चुनावों की दिशा और आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वहीं सरकार इसे सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।

पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता तीन गुना बढ़ा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अध्ययनरत पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या, बड़ी पशुधन संख्या और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण, विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण और उन्मूलन तथा उन्नत नस्लों के संवर्धन में पशु चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत पशु चिकित्सा छात्रों को अब बढ़ा हुआ इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। सरकार के अनुसार वर्तमान में इन छात्रों को 4,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस निर्णय से तीनों विश्वविद्यालयों में अनुमोदित 300 छात्रों को लाभ मिलेगा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में अधिक इंटर्नशिप भत्ता दिए जाने का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रस्ताव लागू होने पर सरकार पर लगभग 4.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा, जिसकी व्यवस्था विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले शासकीय अनुदान के गैर-वेतन मद से की जाएगी। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति रुचि और कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा तथा समानता के सिद्धांत को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसे 'समानता के सिद्धांत' के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मीरजापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी को मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया विस्तार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मीरजापुर जनपद में 'सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी प्रायोजक संस्था को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी स्थित एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े अस्पतालों का सफल संचालन कर रहा है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा मीरजापुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, जिसकी सभी आवश्यक औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद कैबिनेट ने आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के अनुसार यह निजी विश्वविद्यालय मीरजापुर जनपद की चुनार तहसील के ग्राम समसपुर में लगभग 50.45 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के निर्माण से पूर्वांचल क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता भी कम होगी। सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और आधारभूत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, शोध कार्य, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संभावनाओं को भी विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या सीमित थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आठ नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। लंबे समय तक 29 पर स्थिर रहने वाली निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 52 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आठ अन्य संस्थानों को भी आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। माना जा रहा है कि मीरजापुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्वांचल के विद्यार्थियों को नई दिशा मिलेगी और क्षेत्र शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकेगा।

लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सेंटर, कैबिनेट ने दी 855 करोड़ की मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजधानी लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने संस्थान के नवीन परिसर, शहीद पथ स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 में 1010 बेड वाले अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, नवीन ओपीडी ब्लॉक तथा टीचिंग ब्लॉक के निर्माण संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेशवासियों को आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत बनने वाला इमरजेंसी सेंटर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगा। इसमें कुल 1010 बेड स्थापित किए जाएंगे, जिससे गंभीर मरीजों को तत्काल और बेहतर उपचार मिल सकेगा। अस्पताल में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों को राजधानी में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत नया ओपीडी ब्लॉक भी तैयार किया जाएगा। वर्तमान समय में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए ओपीडी ब्लॉक के निर्माण से मरीजों को लंबी कतारों और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी तथा उपचार व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। इसके साथ ही 200 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक टीचिंग ब्लॉक भी विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मेडिकल शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी और छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। चिकित्सा छात्रों को उन्नत प्रयोगशालाएं, डिजिटल शिक्षण सुविधाएं और आधुनिक संसाधनों का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोहिया संस्थान पहले से ही प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल है और अब इस नए विस्तार के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी।

सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सुनीं जन समस्याएं, त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के दिए निर्देश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई एवं जनता दर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने राजस्व विवाद, भूमि संबंधी प्रकरणों तथा अन्य पुलिस मामलों से जुड़ी शिकायतें पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों की गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक जांच की जाए और शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उत्पीड़न की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और पुलिस व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखना प्राथमिक उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है उनमें बिना देरी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

जनसेवा, सुरक्षा व सुशासन सरकार का संकल्प: मुख्यमंत्री योगी

'जनता दर्शन' में आए आमजनों से मिले सीएम योगी, हर आगंतुक की सुनीं समस्या

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले और हर किसी की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि जनसेवा, सुरक्षा व सुशासन सरकार का संकल्प है। आपकी हर उचित समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया। 'जनता दर्शन' में बिहार से भी एक महिला मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं, मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन कर कुशलक्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने सभी के प्रार्थना पत्र लेने के उपरांत सम्बंधित जनपदों के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक स्वयं मामलों पर नजर रखें और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि पूरी तत्परता व संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय मिले। हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। 'जनता दर्शन' में सीएम योगी की प्रशंसक एक महिला बिहार से आई थीं। मुख्यमंत्री सभी की समस्या सुनते हुए उनके पास भी पहुंचे। पूछा कि कहां से आई हैं, आपको क्या परेशानी है। इस पर महिला ने कहा- महाराज जी, प्रणाम। हम बिहार से आइल बानी। हमके कवनो दिक्कत नाही बा। बस आपके दर्शन करेके रहल, त आ गइलीं। इस पर सीएम योगी ने उनका अभिवादन किया, फिर कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में अकारण घर से न निकलें और परिवार के सभी लोगों का भी विशेष ध्यान रखें।

योगी आदित्यनाथ और स्वामी चिदानन्द सरस्वती की लखनऊ में दिव्य भेंट

अयोध्या, प्रयागराज, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विकास पर हुई विस्तृत चर्चा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ऋषिकेश/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती की राजधानी लखनऊ में एक दिव्य और प्रेरणादायक भेंटवार्ता हुई। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और समग्र विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों महान हस्तियों के बीच हुई इस विशेष बैठक को प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में विशेष रूप से अयोध्या और प्रयागराज के विकास को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। दोनों धार्मिक नगरों को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बताते हुए इनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और वैश्विक पहचान को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान यह भी कहा गया कि अयोध्या और प्रयागराज केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक हैं।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश केवल आधारभूत ढांचे, निवेश और औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों के विकास में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का वातावरण मजबूत हुआ है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का विश्वास बढ़ा है। वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि वास्तविक विकास वही माना जाएगा जिसमें संस्कृति, प्रकृति और अध्यात्म का संतुलन बना रहे। उन्होंने नदियों की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने के अभियानों को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गंगा, यमुना और अन्य नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय जीवन और संस्कृति की पहचान हैं। इनकी स्वच्छता और संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कारों और सनातन मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़े रखना जरूरी है। जब युवा अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल भौतिक विकास पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण पर भी समान रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक नगरों का विकास भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया में नई पहचान बना रहा है। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से प्रदेश की छवि लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस दौरान स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि गंगा आरती केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और विश्व शांति का संदेश है। भेंटवार्ता के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी चिदानन्द सरस्वती को प्रभु श्रीराम की दिव्य प्रतिमा और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। दोनों के बीच हुई यह मुलाकात आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण के साझा संकल्प का प्रतीक मानी जा रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरठ के लिए पहली बस ने बिना यात्रियों के भरी रफ्तार

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

प्रयागराज। प्रयागराज से मेरठ के लिए आखिरकार गंगा एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस सेवा की शुरूआत हो गई है। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन के अंतर्गत लीडर रोड डिपो की ओर से इस रूट पर पहली बस को रवाना किया गया। हालांकि, शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और पहले दिन फूलों से सजी इस बस को एक भी सवारी नसीब नहीं हुई। यात्रियों के टोटे के कारण बस अपने निर्धारित समय सुबह दस बजे के बजाय पौने 12 बजे मेरठ के लिए रवाना हुई। रोडवेज प्रशासन ने प्रयागराज से मेरठ तक के इस सफर के लिए प्रति यात्री 839 रुपये का किराया निर्धारित किया है। पहले दिन भले ही बस खाली गई हो, लेकिन विभाग इसे एक महत्वपूर्ण ट्रायल के रूप में देख रहा है। सोमवार को रवाना हुई इस बस के जरिये पूरे रूट का बारीकी से सर्वे किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले ठहराव, समय की उपलब्धता और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में बस की समय सारिणी में बड़ा बदलाव किया जा सकता है।

लीडर रोड डिपो के अधिकारियों के मुताबिक, दिन के समय यात्रियों का रिस्पॉन्स न मिलने के कारण अब इस बस को रात्रि सेवा के रूप में चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि रात के समय एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक हो सकती है। इससे न सिर्फ यात्रियों का दिन का महत्वपूर्ण समय बचेगा बल्कि रोडवेज को भी अच्छा राजस्व मिलेगा।